

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुध,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद,  
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-06 के मुख्य लेखाशीर्षक-2029 व 2052 एवं 2053 तथा 2506 के वचनबद्ध मानक मदों की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक-30 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-06 के मुख्य लेखाशीर्षक-2029 व 2052 एवं 2053 तथा 2506 की संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के वचनबद्ध मानक मदों में स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि को आय-व्ययक की धनराशि में समाहित मानते हुए अवशेष धनराशि ₹1,83,71,62,000=00 (रुपये एक अरब तिरेसठ करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखते हुए नियमानुसार आहरण/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के एक हिस्से हेतु स्वीकृति लेखानुदान की धनराशि को उक्त आय-व्ययक में समाहित माना जायेगा।
2. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012, दिनांक-28 मार्च, 2012 तथा तदक्रम में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अधीन सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करने पर ही धनराशि का आहरण एवं व्यय की जाय।
3. मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधनित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर, बचत सुनिश्चित की जाय।
4. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहां कोई आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फाट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही व्ययमार सृजित किया जायेगा।
5. भारत सरकार द्वारा आयोजनागत (Plan) तथा आयोजनेत्तर (Non-Plan) की व्यवस्था समाप्त कर राजस्व (Revenue) तथा पूंजी की व्यवस्था अपनायी गई है। राज्य सरकार द्वारा भी लेखानुदान राजस्व तथा पूंजी के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया गया है।
6. महालेखाकार द्वारा समय-समय पर आपत्ति के क्रम में विभिन्न विभागों के Minor Head-800 के स्थान पर नये Minor Head खोले जाने की व्यवस्था है।
7. बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक से सम्बन्धित नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में व्यय की प्रतिमाह दिनांक 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
10. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा मानक मद-01-वेतन; 03-महंगाई भत्ता, 06-अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

11. राजस्व मद से पूंजी मद में, इसी प्रकार पूंजी मद से राजस्व मद में पुनर्विनियोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
  12. केन्द्रपोषित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जाय। केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि किसी भी स्थिति में निर्गत नहीं की जायेगी तथा केन्द्र पोषित योजनाओं से किसी अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
  13. वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाय।
  14. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
  15. बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0-10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाय।
  16. इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में प्रचलित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशियां जारी की जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
  17. किसी योजना में धनराशि पी0एल0ए0 में जमा की गयी हो तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय किया जाय तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाय।
  18. प्रत्येक निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में वित्त विभाग की शासनादेश संख्या-475/XXVII(1)/2008 दिनांक-15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो, तो भी समय-सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराने के दृष्टि से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 किया जाय।
  19. चालू निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/परीक्षण सुनिश्चित किया जाय।
  20. अप्रत्याशित व्यय के दृष्टिगत ही अग्रिम धन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से प्रस्ताव किया जाय।
  21. मानक मद के अन्तर्गत प्रतीक (Takan) के रूप में रखी गयी धनराशि का आहरण एवं व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।
02. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-06 के मुख्य लेखाशीर्षक-2029 व लेखाशीर्षक-2052 एवं लेखाशीर्षक-2053 तथा लेखाशीर्षक-2506 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
03. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक-30 जून, 2017 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार/दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
(हरबंस सिंह चुघ)  
सचिव।

संख्या-783 (1)/XVIII(1)/2017-01(30)/2016 TC तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटरर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार (अडिट), वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी/साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(चन्दन सिंह रावत)  
उप सचिव।

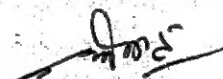
शासनादेश संख्या-783 /XVIII(1)/2017-01(30)/2016 TC, दिनांक-12 जुलाई, 2017 का संलग्नक

राजस्व विभाग		वर्ष 2017-18		
अनुदान सं० 006		(धनराशि हजार में)		
लेखाशीर्षक मानक मद		आय-व्ययक 2017-18 के सापेक्ष लेखानुदान की धनराशि को समाहित करते हुए आवंटित धनराशि		
2029	भू-राजस्व	मतदेय	भारित	योग
001	निदेशन तथा प्रशासन			
03	भूमि अध्यापति-सामान्य राजस्व व्यय			
01	वेतन	20528	-	20528
02	मजदूरी	40	-	40
03	मँहगाई भत्ता	1231	-	1231
06	अन्य भत्ते	1916	-	1916
09	विद्युत देय	33	-	33
10	जलकर जल प्रभार	27	-	27
	योग	23775	-	23775
2029	भू-राजस्व			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
05	राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण			
09	विद्युत देय	167		167
10	जलकर जल प्रभार	167		167
	योग	334		334
029	भू-राजस्व			
101	संग्रहण प्रभार			
03	भू राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार			
01	वेतन	224234		224234
03	मँहगाई भत्ता	13452		13452
06	अन्य भत्ते	20927		20927
	योग	258613		258613
2029	भू-राजस्व			
103	भू-अभिलेख			
03	जिला अधिष्ठान			
01	वेतन	528181		528181
02	मजदूरी	67		67
03	मँहगाई भत्ता	31688		31688



2053	जिला प्रशासन			
101	आयुक्त			
03	मुख्य कार्यालय			
01	वेतन	13326		13326
02	मजदूरी	133		133
03	मँहगाई भत्ता	799		799
06	अन्य भत्ते	1244		1244
09	विद्युत देय	650		650
10	जलकर जल प्रभार	200		200
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1000		1000
17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	73		73
	योग	17425		17425
	योग-2053	622815		622815
2506	भूमि सुधार			
102	चकबन्दी			
03	खेतों की चकबन्दी			
0302	जिला अधिष्ठान			
01	वेतन	46647		46647
02	मजदूरी	33		33
03	मँहगाई भत्ता	2798		2798
06	अन्य भत्ते	4353		4353
09	विद्युत देय	67		67
10	जलकर जल प्रभार	33		33
17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	333		333
	योग-2506	54264		54264
	महायोग (2029+2052+2053+2506)	1637162		1637162

रुपये एक अरब तिरेसठ करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार मात्र

  
(चन्दन सिंह रावत)  
उप सचिव।